



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2023

ज्येष्ठ 3, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ

संख्या 30 / 24-ऊ०नि०नि०प्र०-23-525-2008

लखनऊ, 24 मई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उपधारा (4) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से आस्तियों, दायित्वों, कार्मिकों और सम्बंधित कार्यवाहियों सहित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस०एल०डी०सी०) क्रियाकलापों को उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र लिमिटेड (यू०पी०एस०एल०डी०सी०) को अन्तरित किये जाने और उन निबंधनों और शर्तों को अवधारित करने, जिन पर ऐसा अन्तरण प्रभावी होगा, के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित योजना बनाती हैं:-

1- संक्षिप्त नाम और विस्तार -

(1) यह योजना, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (एस०एल०डी०सी० और आस्तियों, दायित्वों, कार्मिकों एवं सम्बंधित कार्यवाहियों सहित सम्बंधित क्रियाकलापों का अन्तरण) योजना, 2023 कही जायेगी।

(2) यह योजना, यथास्थिति उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की आस्तियों, दायित्वों, कार्मिकों एवं सम्बंधित कार्यवाहियों पर प्रयोज्य होगी।

2- परिभाषाएँ-

(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "आस्तियों" में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, भूमि, भवन, सर्वर, कंप्यूटर और सहायक उपकरण, दूरसंचार प्रणाली, स्टोर, फर्नीचर, फिक्स्ड, वाहन, आवासीय क्वार्टर और अतिथि गृहों एवं उनसे सम्बन्धित सुख सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन, तथा अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनिधान, पुस्तकीय ऋण, भौतिक या अभौतिक, मूर्त और अमूर्त आस्तियां, प्रसुविधाएँ, लाइसेंस, सहमतियां, प्राधिकार, रजिस्ट्रीकरण, लिबरटिस, पेटेंट, व्यापार चिन्ह, विशेषाधिकार, लाभ, प्रसुविधाएं एवं अनुमोदन, संविदाएं, विलेख, योजनाएँ, बंध-पत्र एवं हित, चाहे जिस भी प्रकृति के हों, सम्मिलित हैं;

(ख) "केंद्रीय अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) के अधीन परिभाषित और केंद्रीय अधिनियम की धारा 82 में भी निर्दिष्ट आयोग से है;

(घ) "अन्तरण का दिनांक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अन्तरण योजना की अधिसूचना के दिनांक से है;

(ड) "प्रभावी दिनांक" का तात्पर्य यू०पी० एस०एल०डी०सी० लिमिटेड के निगमन के दिनांक अर्थात् 22.08.2022 से है।

- (च) "दायित्वों" में समस्त दायित्व, ऋण, शुल्क, बाध्यतायें और आकस्मिक दायित्व, वैधानिक दायित्व और किसी प्रकृति के राजकीय शुल्क सहित अन्य जावक सम्मिलित हैं;
- (छ) "कार्मिकों" का तात्पर्य ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से है, जिनमें कर्मकार, अन्तरक प्रशिक्षु, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो, सम्मिलित हैं और अन्तरक से अन्य संगठनों या संस्थानों में प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।
- (ज) "कार्यवाही" में किसी प्रकृति की समस्त कार्यवाहियाँ, वाद, अपील, परिवाद, याचिकाएं, आवेदन, सुलह, मध्यस्थता, चाहे सिविल या आपराधिक या अन्यथा हों, सम्मिलित हैं;
- (झ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अन्तरण योजना से संलग्न अनुसूची से है;
- (ञ) "एस0एल0डी0सी0 उपक्रम" का तात्पर्य अन्तरक द्वारा सम्प्रति उपक्रमित किये जा रहे राज्य भार प्रेषण केंद्र के क्रियाकलापों और उसमें आनुषांगिक या सहायक तथ्यों से संबंधित उपक्रम से है;
- (ट) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
- (ठ) "राज्य अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 से है;
- (ड) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (ढ) "अन्तरक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड से है;
- (ण) "अन्तरिती" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी यू0पी0एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड से है;
- (त) "उपक्रम" का तात्पर्य कृत्यों तथा क्रियाकलापों, आस्तियों, दायित्वों, कर्मियों एवं तत्सम्बन्धित कार्यवाहियों के साथ व्यावसायिक इकाई से है।

(2) इस योजना में प्रयुक्त किन्तु इस योजना में विनिर्दिष्ट रूप से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3-एस0एल0डी0सी0 उपक्रम का अन्तरण-

(1) इस योजना में अन्तर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, अनुसूची में दिये गये एस0एल0डी0सी0 उपक्रम बिना किसी अग्रतर कार्य, विलेख या किसी राज्य सरकार, अन्तरक अथवा अन्तरिती सहित किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य, के प्रयोजन हेतु अधिसूचित अन्तरण, अन्तरण दिनांक से अन्तरिती को अन्तरित एवं निहित माने जायेंगे।

(2) धारा 2(1)(क) और 2(1)(च) के अधीन उपबंधित अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अन्तरक से अन्तरिती को अन्तरित एस0एल0डी0सी0 उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों को अन्तरक के लेखों के अन्तिमीकरण और सम्प्रेक्षण के उपरान्त वास्तविक मूल्य को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाएगा।

(3) इस योजना के अधीन एस0एल0डी0सी0 उपक्रम को इस तरह अन्तरित एवं निहित किये जाने पर, एस0एल0डी0सी0 उपक्रम ऐसे समस्त संविदाओं, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, व्यवस्था, करारों और अन्य लिखतों चाहे वे जिस प्रकृति के हों, जो अन्तरिती को अन्तरित उपक्रम से सम्बन्धित हैं तथा जो अन्तरण के दिनांक को अस्तित्व में थे या प्रभावी थे व जिनमें अन्तरक एक पक्षकार था, के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होंगे जिस प्रकार अन्तरण के दिनांक के ठीक पूर्व अन्तरक उत्तरदायी थे और उन्हें इसी प्रकार प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानों कि अन्तरिती, अन्तरक, के स्थान पर उनका पक्षकार रहा हो।

(4) अन्तरिती को अन्तरित आस्तियों या उपक्रम के अधिकार इस योजना में विनिर्दिष्ट निबंधन और परिसीमाओं के अधीन होंगे।

(5) यदि एस0एल0डी0सी0 उपक्रम में वर्गीकृत आस्तियां किसी प्रभार, धारणाधिकार, विल्लंगम या अन्य करार हेतु किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में किसी वित्तीय सहायता या बाध्यता के लिए प्रतिभूति दस्तावेजों या अन्य व्यवस्थाओं के लिए अन्तरक द्वारा अंगीकृत अथवा गृहीत की गई हो, जो यहां बाद में "प्रतिभूति" के रूप में सन्दर्भित है और अन्तरक द्वारा उसके सम्बन्ध में दायित्वों का पूर्णतः या आंशिक निर्वहन किया जाना हो तो अन्तरक अन्तरिती को ऐसी दी गई सभी प्रतिभूति के लिए उत्पन्न सभी दावों की क्षतिपूर्ति करेगा।

(6) इस योजना के अधीन अन्तरक से अन्तरिती को एस0एल0डी0सी0 उपक्रम का अन्तरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (19 क क) तथा उपरिलिखित उप-खंड (3) के अधीन वर्णित अर्थानुसार अन्तरक का अविलियन होगा, अन्तरण दिनांक को अन्तरिती का प्रारम्भिक तुलन पत्र इस योजना की अनुसूची के भाग-1 के अनुसार होगा।

(7) इस योजना के निबंधनों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 उपक्रम का अन्तरण एवं निहित किये जाने के प्रयोजनार्थ धारा 2(1)(घ) के अधीन अधिसूचित अन्तरण के दिनांक से प्रभावी होगा, बशर्ते कि अन्तरिती के प्रारम्भिक तुलन-पत्र प्रभावी दिनांक पर अन्तरक के लेखों के अन्तिमीकरण, सम्प्रेक्षण तथा वास्तविक मूल्य के समायोजन के अधीन होंगे।

4- तृतीय पक्षकारों के अधिकारों एवं बाध्यताओं का निबन्धित होना-

अधिनियम के उपबंधों और इस योजना के अनुसार अन्तरण प्रभावी होने पर अन्तरिती को योजना के अनुसार अन्तरित एस0एल0डी0सी0 उपक्रम के संबंध में सभी व्यक्तियों (तृतीय पक्षकार) के अधिकार और बाध्यतायें अन्तरिती को निबन्धित होंगे और ऐसे व्यक्ति द्वारा अन्तरक के साथ किये गये किसी विलेख, दस्तावेज, लिखत, करार या व्यवस्था में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वह राज्य सरकार, अन्तरक या अन्तरिती से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधिकार या हित का दावा नहीं करेगा।

5- लम्बित वाद एवं कार्यवाहियां -

(1) एस0एल0डी0सी0 उपक्रम से सम्बन्धित अन्तरण के दिनांक को अन्तरक द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित समस्त कार्यवाहियां, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों, उपशमित या विरत या इस योजना में दिये गये कारणों से अन्यथा प्रतिकूल प्रभावित नहीं होंगी और अन्तरिती द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियों को जारी, अभियोजित और प्रवृत्त किया जा सकेगा।

(2) उपरोक्त उप-खंड (1) में संदर्भित कार्यवाहियों को उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रखा जा सकता है, जैसा कि वे, यदि इस योजना में विनिर्दिष्ट अन्तरण न किये गये होते, अन्तरक द्वारा या उसके विरुद्ध जारी अभियोजित और प्रवृत्त रहतीं या की गई होतीं।

6- अनन्तिम अन्तरण -

(1) इस योजना के अधीन उपक्रम का अन्तरण अनन्तिम होगा।

(2) अन्तिम अन्तरण योजना इस अन्तरण योजना के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनिश्चित की गयी किसी अन्य अवधि के भीतर जारी की जायेगी। अग्रतर यह कि अन्तरण योजना के अन्तिमीकरण के समय उत्तर प्रदेश सरकार अन्तरण की शर्तों व निबन्धनों को ऐसी किसी रीति या ऐसी शर्तों व निबन्धनों पर जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार समुचित समझे, संशोधित, परिवर्तित, उपान्तरित, परिवर्धित, विलोपित या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है।

(3) इस प्रकार अन्तिमीकृत अन्तरण योजना को जारी किये जाने पर उपक्रम, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों का योजना के अनुसार किया गया अन्तरण अन्तिम होगा।

7- अन्तरिती की बाध्यतायें -

(1) अन्तरिती, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32 के अधीन विनिर्दिष्ट अन्तरक के राज्य भार प्रेषण केंद्र दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन करने के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जिस प्रकार अन्तरक अन्तरण के दिनांक से ठीक पूर्व करने के लिए बाध्य था।

(2) अन्तरिती केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग के नियामक नियंत्रण के अधीन राज्य में एस0एल0डी0सी0 गतिविधियों का संचालन करेगा।

8- कार्मिकों का अन्तरण -

(1) कार्मिकों का अन्तरण धारा 133 में निहित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन और केंद्रीय अधिनियम के अन्य लागू उपबंधों के अधीन होगा।

(2) (क) अन्तरण के दिनांक को एस0एल0डी0सी0 में कार्यरत गैर-सामान्य संवर्ग के कार्मिक अस्थायी रूप से उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अन्तरित किये गये माने जायेंगे, जो अन्तरण से ठीक पूर्व में लागू होतीं। यू0पी0पी0टी0सी0एल0 के उपरोक्त गैर-सामान्य संवर्ग के कार्मिक यू0पी0पी0टी0सी0एल0 के कर्मचारी बने रहेंगे और उन्हें यू0पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड से/में अन्तरित किया जा सकता है।

(ख) अन्तरण के दिनांक को एस0एल0डी0सी0 में कार्यरत यू0पी0पी0टी0सी0एल0/यू0पी0पी0सी0एल0 के सामान्य संवर्ग के कार्मिक अस्थायी रूप से अन्तरिती को उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर अन्तरित किये गये माने जायेंगे, जो अन्तरण से ठीक पूर्व लागू होते। ये सामान्य संवर्ग के कार्मिक यू0पी0पी0सी0एल0 के कर्मचारी बने रहेंगे और उन्हें यू0पी0पी0सी0एल0/यू0पी0पी0टी0सी0एल0/यू0 पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड को/से अन्तरित किया जा सकता है।

3- इस तरह के अन्तरण पर और अधिनियम के उपबंधों और इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन, कार्मिक गण अन्तरिती का एक हिस्सा बनेंगे, किन्तु उनकी रैंक, वेतनमान और पारस्परिक ज्येष्ठता को यथास्थिति यू0पी0पी0टी0सी0एल0/यू0पी0पी0सी0एल0 में विद्यमान सामान्य संवर्ग/गैर-सामान्य संवर्ग के लिए, अन्तरण के दिनांक (अन्तरण दिनांक) को बनाए रखा जाएगा और सेवानिवृत्तिक प्रसुविधाएं और अन्य सुविधाएं किसी तरह से यथा स्थिति यू0पी0पी0टी0सी0एल0/यू0पी0पी0सी0एल0 में विद्यमान कार्मिकों से या अन्तरण के दिनांक से ठीक पूर्व उन पर लागू होने वालों से कम अनुकूल नहीं होंगी।

(4) कार्मिकों का अन्तरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात:-

(क) यह कि कार्मिकगण अन्तरण के दिनांक को यथा विद्यमान लागू नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किये जायेंगे, जब तक कि उन्हें समुचित प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाता है;

(ख) अन्तरण पर कार्मिकों के लिए लागू सेवाओं की निबन्धन और शर्तें किसी तरह से अन्तरण के दिनांक से ठीक पूर्व उन पर लागू निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल या निम्नतर नहीं होंगी। तदनुसार, अन्तरण के दिनांक पर लागू सेवाओं प्रसुविधाओं सहित वेतन, भत्ते और अन्य आर्थिक प्रसुविधाएं संरक्षित की जायेंगी।

(ग) ऐसे समस्त कार्मिकों की सेवा में सभी प्रकार से निरंतरता रहेगी;

(घ) अन्तरण के दिनांक से पूर्व प्रोद्भूत सेवा की समस्त प्रसुविधाएं पूर्णतः मान्यता प्राप्त तथा संरक्षित की जाएंगी तथा ऐसे कार्मिकों के किसी और समस्त सेवाओं प्रसुविधाओं के संदाय सहित सम्पूर्ण प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(ङ) कार्मिकों का अन्तरण अग्रतर उन आदेशों के अध्यधीन होगा जो न्यायालयों द्वारा उनकी वरिष्ठता या ऐसे कार्मिकों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य मामलों के सम्बन्ध में अन्तरण के दिनांक को लम्बित कार्यवाहियों में पारित किए जा सकते हैं;

(च) अन्तरण के दिनांक को किसी कार्मिक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों सहित कोई कार्यवाहियाँ जो कदाचार, चूक या कार्यों के संबंध में प्रारम्भ की जा सकती हैं या अन्तरण के दिनांक से पूर्व की गई चूक इस तरह के कार्मिकों के अन्तरण के कारण समाप्त नहीं होगी और इसे अन्तरिती द्वारा जारी रखा जा सकता है मानो इसे अन्तरिती द्वारा प्रारम्भ किया गया हो; और

(छ) इस अन्तरण योजना के कारण कर्मचारियों के बकाया दावों को समाप्त नहीं किया जाएगा।

(5) जहां यथास्थिति यू0पी0पी0टी0सी0एल0/यू0पी0पी0सी0एल0 ने अपने द्वारा नियोजित कार्मिकों की प्रसुविधा के लिए भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो वहाँ उन कार्मिकों, जिनकी सेवाएं इस योजना द्वारा या तत्धीन अन्तरिती को अन्तरित की जायें,से सम्बन्धित संचित धनराशि, जो ऐसी निधि के क्रेडिट में अन्तरण के दिनांक को विद्यमान हो, उपक्रमों के अन्तरिती में निहित होने के दिनांक को पूर्व की भांति तब तक बनी रहेगी, जब तक कि अन्तरिती के कार्मिकों के लिए यथा स्वीकार्य कोई वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है।

(6) एस0एल0डी0सी0 के स्वीकृत पद (अनुसूची-2), एतद्वारा यू0पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड को अन्तरित किये जाते हैं।

9- प्रकीर्ण-

(1) खण्ड 2(1)(घ) के अधीन निहित प्रयोजनार्थ अधिसूचित अन्तरण के दिनांक को इस योजना के अधीन अन्तरण, सांविधिक अन्तरण के रूप में तथा राज्य सरकार, अन्तरक, अन्तरिती या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी अग्रतर कार्य, विलेख या भावी वस्तु के बिना प्रवर्तित एवं प्रभावी होंगे।

(2) यदि केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन इस योजना के अधीन अन्तरणों के संबंध में कोई संदेह, विवाद, मतभेद या विवादक उत्पन्न होता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और समस्त पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(3) राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल ऐसे उपबंध कर सकती है जैसा कि इस योजना के अधीन अन्तरणों को क्रियान्वित करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु आवश्यक प्रतीत हो

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची-1

यू0पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड 22 अगस्त, 2022 का अनंतिम तुलन-पत्र		
विवरण		आंकड़े (रु0में)
आस्तियां		
1-गैर-चालू आस्तियां		
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर		
(एक) संयंत्र व मशीनरी	90,21,710.45	
(दो) फर्नीचर व फिक्चर्स	14,30,649.23	
(तीन) कार्यालय उपस्कर	58,08,636.92	
(चार) अन्य आस्तियां	54,75,442.95	2,17,36,439.55
(ख) अन्य अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर)		36,66,993.02
2- चालू आस्तियां		
भण्डार सामग्री		
		1,62,99,585.87
कुल आस्तियां		4,17,03,018.44
समता व दायित्व		
समता		
समता अंश पूंजी (टिप्पणी-3)		
दायित्व		
1-गैर-चालू दायित्व		
अन्य गैर-चालू दायित्व		
कुल समता व दायित्व		4,17,03,018.44

टिप्पणी:-

1-लखनऊ में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और इसके क्षेत्र/क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर की आस्तियों, यथा संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और फिस्चर्स, कंप्यूटर और सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर और संपत्तियों को यू0पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड को पुस्तक मूल्य पर जैसा है जहाँ है के आधार पर अंतरित किया जाता है।

2- एस0एल0डी0सी0 और क्षेत्र/क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के कब्जाधीन और प्रयुक्त की जा रही भूमि और भवन को यू0 पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड को प्रति वर्ष सांकेतिक किराए पर 1 रुपये (एक रुपये मात्र) के आधार पर पट्टे पर दिया जाता है।

3- प्रारंभिक साधारण पूंजी के लिए सरकार द्वारा एक लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई है, जो यू0पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4- अन्य गैर-चालू देन दारियां ऐसी शेष राशि के रूप में है जो आस्तियों के अन्तरण के विरुद्ध यू0 पी0 पी0टी0सी0एल0 के प्रति संदेय प्रतिफल धनराशि का प्रतिनिधित्व करती है।

अनुसूची-2

एस0एल0डी0सी0 और उसकी अधीनस्थ इकाइयों में पदधारकों तथा कर्मचारियों के स्वीकृत पद		
क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद
क	अधिकारी	
1	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	2
2	अधीक्षक अभियन्ता	6
3	अधिशाली अभियन्ता	26
4	उप मुख्य लेखाधिकारी	1
5	सहायक अभियन्ता	69
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	2
7	लेखाधिकारी	3
योग (क)		109
ख	कार्मिक	
8	लेखाकार	3
9	सहायक लेखाकार	4
10	अवर अभियन्ता	25
11	आशुलिपिक	3
12	कम्प्यूटर आपरेटर(संविदात्मक)	56
13	टी0जी0-।।	5
14	कार्यालय अधीक्षक	1
15	कार्यालय सहायक-।	2
16	कार्यालय सहायक-।।	3
17	कार्यालय सहायक-।।।	15
18	चपरासी	51
	चपरासी (संविदात्मक)एस0एल0डी0सी0	
	चपरासी (संविदात्मक) ए0एल0डी0एस0	
19	स्वच्छकार	4
20	स्वच्छकार (संविदात्मक)	0
योग(ख)		172
कुल योग (क+ख)		281

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 30/XXIV-U.N.N.P-23-525-2008, dated May 24, 2023:

No. 30/XXIV-U.N.N.P-23-525-2008

Dated : Lucknow May 24, 2023

IN exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 131 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) read with sub-section (4) of section 23 of the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (U.P. Act no. 24 of 1999), the Governor is pleased to make the following Scheme for the purpose of transfer of State Load Dispatch Centre (SLDC) activities including the assets, liabilities, personnel and related proceedings from the Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited/Uttar Pradesh Power Corporation Limited, as the case may be, to the Uttar Pradesh State Load Dispatch Centre Limited (UPSLDC), and for determining the terms and conditions on which such transfer shall take effect :

1. Short title and extent –

(1) This Scheme shall be called the Uttar Pradesh Electricity Reform (Transfer of SLDC and Related Activities including the Assets, Liabilities, Personnel and Related Proceedings) Scheme, 2023.

(2) This Scheme shall be applicable to the Assets, Liabilities, Personnel and Related Proceedings of Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited/Uttar Pradesh Power Corporation Limited (As the case may be).

2. Definitions –

(1) In this Scheme unless the context otherwise requires:-

(a) "*Assets*" includes, State Load Dispatch Center, land, buildings, servers, computers & peripherals, telecommunication systems, stores, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts, corporeal or incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, licenses, consents, authorities, registrations, liberties, patents, trademarks, privileges, advantage, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds and interest of whatever nature;

(b) "*Central Act*" means 'The Electricity Act, 2003';

(c) "*Commission*" means the commission defined under the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 (U P. Act No. 24 of 1999) and also referred to in Section 82 of the Central Act;

(d) "*Date of Transfer*" means the date of notification of Transfer Scheme by the State Government;

(e) "*Effective Date*" means the date of incorporation of U P SLDC Limited, i.e. 22.08.2022.

(f) "*Liabilities*" include all liabilities, debts, duties, obligations and other outgoing including contingent liabilities, statutory liabilities and Government levies of whatever nature;

(g) "*Personnel*" means Officers & Employees including Workmen, Trainees of the Transferor, by whatever name called and also includes Officers & Employees on deputation, from the transferor to other organizations or institutions.

(h) "*Proceeding*" includes all proceedings of whatever nature, suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory, arbitration whether civil or criminal or otherwise;

(i) "*Schedule*" means Schedule appended to this Transfer Scheme;

(j) "*SLDC undertaking*" means the undertaking related to the activities of State Load Dispatch Centre presently being undertaken by transferor and acts incidental and ancillary thereto;

(k) "*State*" means the State of Uttar Pradesh;

(l) "*State Act*" means the Uttar Pradesh Electricity Reforms Act, 1999 as amended from time to time;

(m) "*State Government*" means the Government of Uttar Pradesh;

(n) "*Transferor*" means the U.P. Power Transmission Corporation Limited controlled by the State Government;

(o) "*Transferee*" means the U P SLDC Limited, a Government Company incorporated under the Companies Act, 2013;

(p) "*Undertaking*" means the business unit with functions and activities, assets, liabilities, personnel & proceedings related thereto.

(2) Words and expressions used in this Scheme but not specifically defined in this Scheme shall have the same meaning as assigned to them in the Central Act or the State Act.

3. Transfer of SLDC undertaking –

(1) Subject to the terms and conditions contained in this Scheme, the SLDC undertaking as set out in Schedule shall stand transferred to and vest with the Transferee on and from the date of the transfer notified for the purpose without any further act, deed or thing to be done by any person including the State Government, the Transferor or the Transferee.

(2) The assets and liabilities of the SLDC undertaking transferred from the Transferor to the Transferee as specified in the Schedule-1 as on 'Effective Date' of transfer, provided under clause 2(1)(a) and 2(1)(f) and shall be adjusted to reflect the actual value on finalization and audit of accounts of the Transferor.

(3) On such transfer and vesting of the SLDC undertaking in terms of this Scheme, the Transferee shall be responsible for all contracts, rights, deeds, schemes, arrangement, agreements and other instruments of whatever nature relating to the SLDC Undertaking transferred to the Transferee to which the Transferor was a party, subsisting or having effect on the date of the transfer in the same manner as the Transferor was liable immediately before the date of the transfer and the same shall be in force and effect against or in favour of the Transferee and may be enforced effectively as if the Transferee had been a party thereto instead of the Transferor.

(4) The rights in the assets or undertaking transferred to the Transferee shall be subject to the restrictions and limitation specified in this scheme.

(5) If the assets classified as a part of the SLDC undertaking are subject to any charge, lien, encumbrance or other arrangement in favour of third parties for any financial assistance or obligation taken or assumed by the Transferor hereinafter referred to as "Security" and the liabilities in respect thereof are to be discharged either wholly or partly by the Transferor, the Transferor shall indemnify the Transferee from all claims arising out of the enforcement of such security.

(6) The transfer of the SLDC undertaking from the Transferor to the Transferee under this Scheme shall be a de-merger of the Transferor within the meaning of Section 2 (19AA) of the Income Tax Act, 1961 and subject to sub-clause (3) above, the opening Balance sheet of the Transferee as on the date of the transfer shall be as per Schedule-1 of this scheme.

(7) The transfer and vesting of the SLDC undertaking in terms of this Scheme shall take effect on the date of the transfer notified for the purpose under clause 2(1)(d), notwithstanding that the opening balance-sheet of the Transferee is subject to finalization of accounts of the Transferor as on Effective Date and adjustment of the actual values and audit thereof.

4. Rights and obligations of third parties restricted –

Upon the transfer being effected in accordance with the provisions of the Act and this scheme, the rights and obligations of all persons (third parties) in regard to the SLDC undertaking transferred to the Transferee as per this scheme shall be restricted to the Transferee and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Transferor, he shall not claim any right or interest against the State Government, the Transferor or any person other than the Transferee.

5. Pending suits and proceedings –

(1) All proceedings of whatever nature by or against the Transferor pending on the date of the transfer relating to the SLDC undertaking shall not abate or discontinue or otherwise in any way prejudicial be affected by reason of this scheme and the proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the Transferee.

(2) The proceedings referred to in sub-clause (1) above may be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Transferor if the transfers specified in this scheme had not been made.

6. Transfer provisional –

(1) The transfer of undertaking under this scheme shall be provisional.

(2) The final Transfer Scheme shall be issued within one year from the date of issuance of this Transfer Scheme or the any other period decided by Government of Uttar Pradesh. Further while finalising the Transfer Scheme, Government of Uttar Pradesh may amend, vary, modify, add, delete or otherwise change terms and conditions of the transfer in such manner and on such terms and conditions as Government of Uttar Pradesh may consider appropriate.

(3) On issue of such Transfer Scheme so finalised, the transfer of undertaking, properties, interests, rights, liabilities and proceedings made in accordance with the scheme shall become final.

7. Obligations of the Transferee –

(1) The Transferee shall be responsible to duly discharge the State Load Despatch Centre obligations of the Transferor as specified under section 32 of the Electricity Act, 2003 in the same manner as the Transferor was bound to immediately before the date of the transfer.

(2) The Transferee shall undertake the SLDC activities in the State under the regulatory control of the Commission as per the provisions of the Central Act and State Act.

8. Transfer of Personnel –

(1) The transfer of Personnel shall be subject to the terms and conditions contained in Section 133 and other applicable provisions of the Central Act.

(2) (a) The Non-Common Cadre personnel working in SLDC on Date of Transfer shall stand provisionally transferred to the transferee on the same term and conditions as would have been applicable immediately prior to transfer. The above Non- Common Cadre personnel of UPPTCL will remain the employees of UPPTCL and can be transferred to/ from U P SLDC Limited.

(b) The Common Cadre personnel of UPPTCL/UPPCL working in SLDC on the Date of Transfer shall stand provisionally transferred to the Transferee on the same terms & conditions as would have been applicable immediately prior to Transfer. These Common Cadre personnel will remain the employees of UPPCL and can be transferred to/from UPPCL/UPPTCL/ U P SLDC Limited.

(3) On such transfer and subject to the provisions of the Act and other provisions of this Scheme, the personnel shall form a part of the Transferee, but their rank, scale of pay and inter-se seniority as existing in the UPPTCL/UPPCL (as the case may be) for Common Cadre/ Non-Common Cadre, on the date of transfer (Transfer Date) shall be maintained and the retirement benefits and other facilities shall in no way be less favourable than the one existing in the UPPTCL/UPPCL (as the case may be), or inferior to those applicable to them immediately before the Date of Transfer.

(4) The transfer of the personnel shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) That the personnel shall be governed by the applicable Rules and Regulations existing as on the Date of Transfer till the same is varied or revised in accordance with law by the appropriate authority;

(b) The terms and conditions of the services applicable to the personnel on transfer shall not in any way be less favourable than or inferior to those applicable to them immediately before the Date of Transfer. Accordingly, the salary, allowances and other pecuniary benefits including terminal benefits applicable on the Date of Transfer shall be protected.

(c) All such personnel shall have continuity of service in all respects;

(d) All benefits of service accrued before the Date of Transfer shall be fully recognized and protected and taken into account for all purposes including for payment of any and all terminal benefits of such Personnel;

(e) The transfer of Personnel shall be further subject to the orders that may be passed by the Courts in the proceedings pending as on the Date of Transfer in regard to their seniority or other matters concerning the service conditions of such personnel;

(f) Any proceedings including disciplinary proceedings pending against any Personnel as on the Date of Transfer or which may be initiated in relation to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the Date of Transfer shall not abate by reason of transfer of such Personnel and the same may be continued by the Transferee as if the same had been initiated by Transferee; and

(g) The outstanding claims of employees shall not be extinguished because of this Transfer Scheme.

(5) Where UPPTCL/UPPCL (as the case may be), has established a provident fund or any other fund, for the benefit of the Personnel employed by it, the accumulated amount relating to the Personnel whose services are transferred, by or under this Scheme to Transferee standing as on Date of Transfer to the credit of such fund shall on the date of vesting of the Undertakings in Transferee, continue as before until such time that an alternate mechanism is developed as acceptable to the Personnel of Transferee and the same is implemented.

(6) The sanctioned post of SLDC (Schedule -2) is hereby transferred to U P SLDC Limited.

9. Miscellaneous –

(1) The transfers under this scheme shall operate and be effective on the date of transfer notified for the purpose under clause 2(1)(d) as a statutory transfer and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, the Transferor, the Transferee or any other person.

(2) If any doubt, dispute, difference or issue shall arise in regard to the transfers under this scheme, subject to the provisions of the Central Act, the decision of the State Government thereon shall be final and binding on all parties.

(3) The State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under this scheme.

SCHEDULE-1

U P SLDC Ltd. PROVISIONAL BALANCE SHEET AS AT 22 nd AUGUST, 2022		
Particulars		Figures in Rs.
ASSETS		
1. Non-current Assets		
(a) Property, Plant & Equipment		
i. Plant & Machinery	90,21,710.45	
ii. Furniture & Fixture	14,30,649.23	
iii. Office Equipment	58,08,636.92	
iv. Other Assets	54,75,442.95	2,17,36,439.55
(b) Other Intangible Assets (Software)		36,66,993.02
2. Current Assets		
Inventories (Capital)		1,62,99,585.87
Total Assets		4,17,03,018.44
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity		
Equity Share Capital (Note -3)		-
Liabilities		
1. Non-Current Liabilities		
Other Non-Current Liabilities		4,17,03,018.44
Total Equity & Liabilities		4,17,03,018.44

Note :-

1. Assets of the State Load Despatch Centre at Lucknow and its Area/Regional Load Despatch Centres, like Plant & Machinery, Furniture & Fixtures, Computer & Peripherals, Software, other Assets are transferred on as is where is basis to U P SLDC Limited at book value.
2. Land and Buildings being in possession & used by SLDC & Area/Regional Load Despatch Centre are given on lease basis at token rent of Re.1 (Rupee One Only) per annum to U P SLDC Ltd.
3. An amount of rupees one lakh has been sanctioned by the Government towards initial Equity Capital which is yet to be received by UPSLDC Limited.
4. Other Non-Current Liabilities is the balancing figure which represents the consideration amount payable to UPPTCL against transfer of Assets.

SCHEDULE-2

Sanctioned posts of officials and employees in S.L.D.C. and its subordinate Units		
Sl. No.	Designation	Sanctioned Post
A	Officers	
1	Chief Engineer (Level-1)	2
2	Superintendent Engineer	6
3	Executive Engineer	26
4	Deputy Chief Accounts Officer	1
5	Assistant Engineer	69
6	Senior Accounts Officer	2
7	Accounts Officer	3
Total (A)		109

Sanctioned posts of officials and employees in S.L.D.C. and its subordinate Units		
Sl. No.	Designation	Sanctioned Post
B	Personnel	
8	Accountant	3
9	Assistant Accountant	4
10	Junior Engineer	25
11	Stenographer	3
12	Computer Operator (Contractual)	56
13	Technical Grade-II	5
14	Office Superintendent	1
15	Office Assistant-I	2
16	Office Assistant-II	3
17	Office Assistant-III	15
18	Peon	51
	Peon (Contractual) SLDC	
	Peon (Contractual) ALDS	
19	Sweeper	4
20	Sweeper (Contractual)	0
Total (B)		172
Grand Total (A+B)		281

By order,
 MAHESH KUMAR GUPTA,
Apar Mukhya Sachiv.